अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को देय 217.07 करोड़ रूपये के सामान्य हिस्से से 7.93 करोड़ रूपये अधिक की एससीए उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 1997-98 में उत्तरांचल पर्वतीय क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है, अर्थात 1.82 करोड़ रू0 पुलों के लिए 1.40 करोड़ रूपये ट्यूबवैलों के लिए और नैनीताल झील से संबंधित कार्यो के लिए 0.80 करोड़ रूपये।

1998-99 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रो के लिए एचएडीपी के अन्तर्गत 237.41 करोड़ रूपये की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और इसके अलावा 25 करोड़ रूपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं।

Schedule of Ninth Plan

604. SHRI YOGINDER K. ALAGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the schedule of preparation of the Ninth Plan has been inordinately delayed; and

(b) the impact of this delay and the revised schedule?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The Draft Ninth Five Year (1997-2002), approved at internal meetings of the Planning Commission was released on March 1, 1998 by the then Deputy Chairman, Planning Commission. The Government has decided to review this Draft so as to suitably reflect the altered priorities, as enunciated in the National Agenda for Governance. Detailed action plans on the above guidelines have been prepared and suitably incorporated to the existing Draft. The new Draft Ninth Five Year Plan has been discussed at the meetings of the internal Planning Commission and Full Planning Commission. This revised document is to be submitted through due process for consideration and approval of National Development Council.

Schemes Proposed by MPs of Eleventh Lok Sabha

605. SHRI DAWA LAMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government arc aware that many MPs of Eleventh Lok Sabha have submitted list of MPLADS during 1997-98 and during their incumbencies and funds have not been provided to those schemes which are yet to be executed: and

(b) the action proposed to implement the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The works recommended by the MPs of XI Lok Sabha arc required to be executed according to the priciplcs contained in para 3.9 of the guidelines on MPLADS. Funds to complete these eligible works have been provided/are being provided as per the entitlement of the MP.

सूरत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

606. **श्री गोपाल सिंह जी 0 सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने गुजरात के सूरत शहर में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए दो अरब रूपये की सहायता राशि जारी करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कल कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने सूरत में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनएफसीआर) से 200 करोड़ रू0 की सहायता मांगते हुए एक ज्ञापन दिया है । इस ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा

607. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है जहां चालीस प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त योजना में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है, यहां आजीविका के संसाधन जुटाने के लिए लोगो को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किन-किन योजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव हैं और इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को जितना लाभ पहुंचेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीराम नाईक) : (क) से (घ) राज्य के विकास का उत्तरा दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है । तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है । गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन हेतु ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों में एकीकृत ग्रामी विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) शामिल है । इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) अशिक्षित, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है । विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रो, पर्वतीय क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जनजाति उप-योजना जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं ।

Fund Allocation for Gokul Gram Yojana

608. SHRI' BRAHMAKUMAR BHATT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a proposal from the Government of Gujarat for allocation of funds for the implementation of "GOKUL GRAM YOJANA";

(b) if so, the details of the proposal and the funds allocated to the State Government;

(c) whether Government are planning to enforce the scheme to other states also; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The Government of Gujarat have included the scheme of Kokul Gram Yojana in their Annual Plan 1998-99. The scheme aims at providing basic infrastructure to all the villages within a time frame of five years. Under the Scheme, twelve activities have been identified for this purpose. These include, all weather approach road, drinking water, construction of village ponds with bathing ghats, renovation of existing takns, community latrines, soak pit and soak wells for village cleanliness, building for primary schools, community halls, community work sheds, village afforestation and electrification etc. For the annual plan 1998-99, the State Government have allocated Rs. 15,000 lakhs to cover 10932 villages. During discussion with the Deputy Chairman at the time of finalization of the Annual Plan, Chief Minister rquested for